12.00 Noon

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; the time is over. It is time for Question Hour.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair)*

ORAL ANSWERS TO THE QUESTIONS

*76 **[The Questioner (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR) was absent]**

Depletion of coal reserves

*76. SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the production of coal has increased during the last few years, if so, the details thereof;

(b) the rate of increase compared to the gross domestic product during the last two years; and

(c) whether the coal reserves in the country are depleting fast, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI PIYUSH GOYAL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) All India coal production has increased from 565.77 Mte in 2013-14 to 638.18 Mte. (prov.) in 2015-16. The details of coal production during last three years is as under.

(in million tonnes)

Production	2013-14	2014-15	2015-16
All India	565.77	609.18	638.18
Growth %	1.7	7.7	4.8

Further, Coal India Limited (CIL) produces around 80% of the country's total production of coal. It has increased its production from 462.41 Mte. in 2013-14 to 538.75 Mte. in 2015-16. The increase of 76 Mte in actual production achieved by CIL in last two

years is more than the cumulative increase achieved during the 11th 5 year plan. CIL's production in last 3 years is given below:

(in million tonnes)

Production	2013-14	2014-15	2015-16
CIL	462.41	494.23	538.75
Growth %	2.3	6.9	9.0

(b) The details of rate of increase of coal production compared to GDP during last two years are given below:-

Year	Rate of increase in coal production over last year (%)	Rate of Increase (Growth) in GDP* (%)
2014-15	7.7	7.24
2015-16	4.8	7.56

**Source:* GDP-CSO - (GDP data is at constant price). Coal production - CCO.

(c) Coal reserves are not depleting. Every year about 3 to 5 BT coal resources are added to the inventory of Indian coal resources and against this, about 0.65 Bt. coal is extracted.

MR. CHAIRMAN: Question No. 76; questioner not present. Are there any supplementaries?

श्री हरिवंशः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कोयला राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की मांग में पहले की अपेक्षा कमी आई है? हम कब तक कोयले के उत्पादन के बारे में आत्मनिर्भर होंगे और आज हम अपनी जरूरत का कितना कोयला बाहर से मंगाते हैं?

श्री पीयूष गोयलः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों में कोयले की डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, उल्टे पावर प्लांट्स का जो आउटपुट है, अगर आप उसका आकलन करें, तो गत 10 वर्षों में, 2004 से 2014 तक, बिजली के उत्पादन में 5.65 परसेंट की वृद्धि हुई थी। यह गत 10 वर्षों की CAGR की figures हैं और 2014 से 2016 मात्र 2 वर्षों की हमारी जो पावर प्रोडक्शन की ग्रोथ है, वह 7.03 परसेंट रही है, जिससे ध्यान में आता है कि बिजली का उत्पादन भी बढ़ रहा है और बिजली की खपत भी बढ़ रही है।

साथ ही साथ, ये दोनों वर्ष सूखे के वर्ष हैं और सूखे के कारण जो हाइड्रो पावर कम उत्पादित हुई, उसके बावजूद देश में कहीं भी बिजली की आपूर्ति में कमी नहीं हुई। आज देश power surplus है। जो कमी हाइड्रो पावर में आई, उसको हमने कोयले से बिजली के उत्पादन को बढ़ा कर पूरा किया और देश में जितनी बिजली जो राज्य चाहते हैं, उनको हम देने की स्थिति में आज आ गए हैं।

आपने दूसरी बात यह कही कि देश कब तक कोयले के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होगा, तो इसमें दो प्रकार का कोयला है, एक कोकिंग कोल है और दूसरा थर्मल कोल है। जहां तक कोकिंग कोल का सवाल है, तो देश में इसका प्रोडक्शन कम है, यह कमी सालों-साल से रही है। हर वर्ष 45 से 50 मिलियन टन कोकिंग कोल इम्पोर्ट होता है, क्योंकि यहां कोकिंग कोल के नये रिंजव्स भी या तो कम हैं या वे आग के नीचे हैं, जैसे झरिया या रानीगंज में। इसके कारण कोकिंग कोल का आयात कुछ और वर्षों तक कंटीन्यू रहेगा, जब तक हम नये रिंजव्स डेवलप नहीं करेंगे।

जहां तक थर्मल कोल का सवाल है, तो उसके इम्पोर्ट में पिछले वर्ष 24,000 करोड़ रुपये की कमी हुई, क्योंकि हमने उसको डोमेस्टिक कोल से रिप्लेस किया। इस वर्ष का टारगेट है कि इस इम्पोर्ट को हम 40,000 करोड़ कम करेंगे। जहां-जहां इम्पोर्टेड कोल यूज़ होता है, उसको हम कम करके डोमेस्टिक से रिप्लेस करना चाहते हैं। एक समस्या जरूर है कि जो कोस्टल प्लांट्स हैं, वे ओरिजिनली डिजाइंड ही इम्पोर्टेड कोल पर हुए। भारत का जो हाई फ्लाई ऐश का कोल है, उसे लेने के लिए वे सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उस जमाने में कभी यह कल्पना ही नहीं की गई कि भारत कोल प्रोडक्शन इतनी बढ़ सकता है और कोल के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। चूंकि वह डिजाइन भारत के कोल को नहीं लेता है, तो जबरन भारत को काफी कुछ कोल इम्पोर्ट करने की आगे आवश्यकता पड़ेगी।

श्री राम विचार नेतामः सभापति महोदय, मैं इसमें एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो उत्तर दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह बात सही है, लेकिन हम पूरे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जहां-जहां कोल का उत्पादन हो रहा था, करीब एक-एक महीने का वहां डम्प पड़ा हुआ है। तो आपका जो मापदंड है, उस मापदंड के आधार पर कितने दिनों का स्टोरेज करने की आपकी क्षमता होती है? इसी के साथ, इसके लिए क्या आपका कोई नीतिगत सिद्धांत है कि क्या कोयले की जो खपत है, उसमें कमी आई है? और अगर खपत में कमी आई है, तो विद्युत उत्पादन में भी कमी आ सकती है या डिमांड में कमी आ सकती है? इस तरह के जो प्रश्न हैं, ये एक-दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं किं आप इस सबंध में क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उत्पादन के बाद वहां पर जो लगातार डम्प का डम्प पड़ा हुआ है, इसके लिए कहीं जगह नहीं है और भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसको रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं?

श्री पीयूष गोयलः सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरेक खान के पास एक कोल स्टॉक रहता है, उसको pithead stock कहते हैं और हर खदान के पास कितना स्टॉक रखा जा सकता है, इसका कोई दिनों में आकलन नहीं होता है, वह stocking capacity के हिसाब से हर माइन के साथ जुड़ा हुआ एक आंकड़ा रहता है। मैं माननीय सांसद को यह भी बताना चाहूंगा कि 31 मार्च, 2016 को लगभग 57 मिलियन टन का स्टॉक कोल इंडिया के अलग-अलग subsidiaries की अलग-अलग खदानों में था, अब घट कर जिसकी लेटेस्ट फिगर 47 मिलियन टन हो गयी है। उसको हमने और aggresively e-auction के द्वारा, special auction के द्वारा और exclusive auction के द्वारा liquidate करके उस स्टॉक को भी कम किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि देश की आत्मनिर्भरता और देश की ऊर्जा सुरक्षा और हमारे उद्योगों को, छोटे व्यापारियों की requirements को मद्देनज़र

रखते हुए एक अच्छा स्टॉक कोल इंडिया रखे ताकि कभी भी कोई disaster हो या कोई ऐसी तकलीफ आए, तो इस देश में कोल की कमी न हो, इसलिए हम वह स्टॉक रखते हैं।

आपका दूसरा सवाल, ऊर्जा की कमी या कोल उत्पादन की कमी के संबंध में था, उसका जवाब तो अभी-अभी मैंने बड़े विस्तार से दिया।

श्री रेवती रमन सिंहः चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश में अभी तीन पावर प्लांट्स लग रहे हैं, उनमें एक तो एनटीपीसी का है मेजा में, दूसरा जेपी का है बारा में और तीसरा करछना में प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और एनटीपीसी के प्लांट ने कितने कोयले की डिमांड की थी और आपने कितना देने का काम किया है?

श्री पीयूष गोयलः सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता और सांसद ने, जो कि इनके ही पार्टी के हैं, उन्होंने सदन में एक बार मेरे ऊपर यह आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोयला कम है। मैंने उसी दिन दोपहर में आंकड़े रखे, जिसमें मैंने बड़े विस्तार से बताया था कि जब भारत में प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई, तब उत्तर प्रदेश या देश के अलग-अलग बिजली घरों में कोयले की कमी रहती थी, लेकिन आज के दिन परिस्थिति ऐसी है कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली घर ऐसा नहीं है, जिसमें कोयलेकीकमीहै।उल्टे,मैंबार-बाररिव्यूकरताहूं।गतमहीनेहीमैंउत्तरप्रदेशमेंजाकरलखनऊमें
पूरा रिव्यू करके आया। वहां पर हर बिजली घर में बताया गया कि हमारे पास पर्याप्त कोयला है और मेहरबानी करके और मत भेजिए। यह भी हम से दरख्वास्त की गई।

जहां तक नए प्लांट्स का सवाल है। जितना कोयला जिस प्लांट को लगेगा, उतना कोयला उसको मिलेगा। जहां तक एनटीपीसी का सवाल है, उसको तो हम सीधा allot कर सकते हैं और जो दूसरे प्राइवेट प्लांट्स हैं, उनको हम auction के माध्यम से पारदर्शिता से देंगे, लेकिन इस देश में जितने पावर प्लांट्स लगते हैं, सबको कोयला देने की आज देश में क्षमता है।

उत्तर प्रदेश के गांवों का विद्युतीकरण

*77. **श्री नरेश अग्रवाल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी पचास प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ; है

(ख) यदि हां, तो सरकार सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की है और केन्द्रीय सरकार ने इसके अंतर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध करायी है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।